छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

सिविल रिट क्षेत्राधिकार

सिविल रिट याचिका संख्या: 3556 / 2003

विषय में:

रेलटेक स्क्रेटर सिस्टम्स,

जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है:

119, एवेन्यू लुई रोश —

बीपी 152, 92231

जेनेविलियर्स सेडेक्स,

फ्रांस

— द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक एवं सहयोगी

श्री एम. सिरिल पिडूक्स,

... याचिकाकर्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बनाम

1. भिलाई स्टील प्लांट,

   प्रशासनिक ब्लॉक,

   भिलाई – 490001,

   जिला दुर्ग,

   छत्तीसगढ़

   —द्वारा प्रबंध निदेशक

   श्री बी.के. सिंह;

2. उप महाप्रबंधक (परियोजना – ई.पी.एस.),

   प्रशासनिक ब्लॉक,

   भिलाई स्टील प्लांट,

   जिला दुर्ग,

   छत्तीसगढ़;

3. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,

प्रधान कार्यालय:

इस्पात भवन,

लोधी रोड,

नई दिल्ली – 110003

—— द्वारा अध्यक्ष;

4. मेसर्स मेकेलोनिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड,

प्रधान कार्यालय:

C–230, सोलारिस–1,

साकीविहार रोड,

पवई, मुंबई – 400072

—— द्वारा अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक,

... उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रकरण के संबंध में:

यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें उत्प्रेषण अथवा उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश की मांग की गई है, जिससे सुसंगत अभिलेख को न्यायालय में प्रस्तुत कराया जा सके, जो निम्नलिखित निविदाओं से संबंधित है:

- **निविदा संख्या IFB No.CE(TK)/5(338)A/2003/437, दिनांक 29.03.2003 (पैकेज A के लिए)**
- **निविदा संख्या IFB No.CE(TK)/5(338)B/2003/438, दिनांक 31.03.2003 (पैकेज B के लिए)**

और

एक उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश पारित करने की भी प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अगस्त 2003 में उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में जारी लेटर ऑफ इंटेंट और उसके पक्ष में आगे निष्पादित किसी भी अन्य संविदा/दस्तावेज को अवैध, निविदा की शर्तों के विपरीत और गैरकानूनी मानते हुए अभिखंडित और अपास्त किया जाए।

और

एक परमादेश रिट (Mandamus) अथवा उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश पारित करने की प्रार्थना की गई है, जिससे उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता कंपनी के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेंट जारी करें, और तत्पश्चात निम्नलिखित निविदाओं के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज (संविदा सहित) निष्पादित करें:

- **IFB No.CE(TK)/5(338)A/2003/437, दिनांक 29.03.2003 (पैकेज A)**
- **IFB No.CE(TK)/5(338)B/2003/438, दिनांक 31.03.2003 (पैकेज B)**

और मामले में:–
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका संख्या: 3336 / 2003</u>

रेलटेक स्कलेटर सिस्टम्स

बनाम

भिलाई स्टील प्लांट एवं अन्य

<u>आदेश</u>

मामला निर्णय हेतु दिनांक: 12 / 04 / 2004 को नियत।

सही /—

फखरुद्दीन

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या: 3556 / 2003

रेलटेक स्कलेटर सिस्टम्स

बनाम

भिलाई स्टील प्लांट एवं अन्य

प्रतिनिधित्व:

- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजीव दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर.एस. जायसवाल, अधिवक्ता के साथ
- उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से: श्री विजय हंसरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी. दिवाकर, अधिवक्ता के साथ
- उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से: श्री रविंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मनींद्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता के साथ

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश द्वारा:

याचिकाकर्ता ने यह याचिका रिट उत्प्रेषण अथवा अन्य उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश जारी करने के लिए दायर की है, जिसके माध्यम से निम्नलिखित निविदाओं से संबंधित अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकें निविदा क्रमांक CE(TK)/5(338)A/2003/437, दिनांक 29.03.2003 (पैकेज A के लिए); तथा निविदा क्रमांक CE(TK)/5(338)B/2003/438, दिनांक 31.03.2003 (पैकेज B के लिए); जो कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 द्वारा जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी प्रार्थना की है कि एक उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश पारित किया जाए, जिसके द्वारा अगस्त 2003 में उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में जारी किए गए आशयपत्र और उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी अन्य संविदा / दस्तावेज को अभिखंडित और ख़ारिज कर दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार ये कार्य अवैध है, और निविदा की शर्तों के विपरीत किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि एक परमादेश रिट (Mandamus) या उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो कि मंडामस की प्रकृति का हो, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को याचिकाकर्ता कंपनी के पक्ष में आशयपत्र जारी करने, तथा इसके पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेजों का, संविदा आदि सहित,निविदा के संबंध में निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया जा सके।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता एक कंपनी है जो कि फ्रांस गणराज्य के कानूनों के अंतर्गत विधिवत रूप से पंजीकृत है, और यह विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग उपकरणों के निर्माण एवं बिक्री के व्यवसाय में संलग्न है, जिसमें रेल वेल्डिंग संयंत्र भी शामिल हैं। कहा गया है कि वे दुनिया के अग्रणी निर्माता एवं एकीकर्ता हैं, जिन्हें वेल्डिंग संयंत्रों के निर्माण और आपूर्ति का बहुत व्यापक अनुभव प्राप्त है। यह भी कहा गया है कि वे रेल फ़्लैश बट वेल्डिंग मशीनों सहित अन्य फिनिशिंग उपकरणों का निर्माण और वितरण विभिन्न देशों को पूर्व में कर चुके हैं। यह तर्क दिया गया है कि वे वर्तमान में भारत में जिंदल स्टील एंड पावर के लिए उसी प्रकार की मशीनों की आपूर्ति कर रहे हैं। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी को यह याचिका दायर करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 ने गैरकानूनी ढंग से और मनमाने ढंग से कार्य करते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 4 कंपनी को आशयपत्र जारी करने तथा पैकेज A और B का संविदा प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो कि निविदा की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन में है, जैसा कि: IFB संख्या

CE(TK)/5(338)A/2003/437 दिनांक 29.03.2003 (पैकेज A) तथा IFB संख्या CE(TK)/5(338)B/2003/438 दिनांक 31.03.2003 (पैकेज B) में निहितत्व था। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त कार्यवाही कानून के विरुद्ध है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। यह भी कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा किया गया यह कार्य मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग है, जो कि भारत सरकार के कार्यकारी निकाय / उपक्रम होने के नाते अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "राज्य" की परिभाषा में आते हैं।

3. याचिकाकर्ता द्वारा विचारार्थ विधिक प्रश्न इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं:

(क) क्या जब सरकार निविदा के माध्यम से संविदा प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो क्या उसे निविदा की शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है, और यदि वह ऐसा नहीं करती तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा?

(ख) क्या वर्तमान मामले में उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट जारी करना और उत्तरवादी क्रमांक 4 को संविदा प्रदान करना —निविदा संख्या CE(TK)/5(338)A/2003/437 दिनांक 29.03.2003 (रेल वेल्डिंग मशीन हेतु) निविदा संख्या CE(TK)/5(338)B/2003/438 दिनांक 31.03.2003 (फिनिशिंग मशीन और कन्वेयर हेतु) क्या यह कार्य दुर्भावना, अयुक्तियुक्तता और मनमानेपन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) के अंतर्गत में आता है?

4. श्री राजीव दत्ता, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2002 में उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा एक विश्व-स्तरीय रेल वेल्डिंग संयंत्र को रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल में स्थापित करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय रेलों की 240 से 260 मीटर लंबी रेल पट्टियों की मांग को पूरा करना, ताकि सुरक्षित एवं उच्च गति यात्रा सुनिश्चित की जा सके। यह तर्क भी दिया गया कि याचिकाकर्ता कंपनी ने निविदा दस्तावेज खरीदे थे। निविदा दस्तावेज खरीदने के पश्चात, याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रस्तावित बोली दिनांक 14/08/2002 को प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता एकमात्र पात्र बोलीदाता था, किन्तु दुर्भाग्यवश, विस्तृत तकनीकी और वाणिज्यिक बातचीत के पश्चात, उत्तरवादियों ने निविदा को रद्द कर दिया, जिसका उल्लेख दिनांक 31/03/2003 के पत्र द्वारा किया गया। यह कहा गया कि रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 ने फिर से एक वैश्विक निविदा जारी की जो कि पूर्ण रेल वेल्डिंग संयंत्र और रेल स्ट्रक्चरल मिल की खरीद हेतु थी, किन्तु इस बार मूल एकीकृत संयंत्र को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया:

High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) पैकेज 'A' — रेल वेल्डिंग मशीन की संस्थापन;

(ii) पैकेज 'B' — रेल वेल्डिंग संयंत्र के उपकरणों की संस्थापन, जैसे:

- रोलर टेबल्स,
- ट्रांसफर बेड,
- ब्रशिंग स्टेशन,
- ग्राइंडिंग स्टेशन,
- हाइड्रोलिक प्रेस,
- कूलिंग स्टेशन,
- अल्ट्रासोनिक फ़्लॉ डिटेक्टर,
- आरी (Saws),
- बेंड टेस्ट मशीन आदि;

(iii) पैकेज 'C' — रेल वेल्डिंग संयंत्र – रेल हैंडलिंग प्रणाली का संस्थापन।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालाँकि याचिकाकर्ता ने तीनों निविदा दस्तावेज खरीदे थे, लेकिन उसने केवल पैकेज A और पैकेज B के लिए ही अपनी बोली प्रस्तुत की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 द्वारा दो निविदा आमंत्रण दिनांक 29.03.2003 और 31.03.2003 को याचिकाकर्ता को भेजे गए। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 द्वारा बिड डाटा शीट संलग्न की गई थी, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में दाखिल की गई है। यह भी कहा गया कि यह विवरण निविदा दस्तावेजों में समाहित था। निविदा आमंत्रण, जो याचिकाकर्ता को भेजे गए थे, उनमें उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 ने पैकेज A के लिए

बायोडाटा शीट भी सम्मिलित की थी, जो कि ITB 8.3 (c) के अंतर्गत आती है, जिसमें बोलीदाता की पात्रता के लिए मानदंड इस प्रकार निर्दिष्ट थे:

(i) प्रमुख बोलीदाता को पिछले 5 वर्षों में कम से कम 5 (पांच) स्वतः फ़्लैश बट रेल वेल्डिंग मशीनों की सफल आपूर्ति एवं स्थापना करना चाहिए था।

(ii) प्रमुख बोलीदाता का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार ₹4.00 करोड़ (लगभग) होना चाहिए।

6. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पैकेज B के लिए बिड डाटा शीट में ITB 8.3 (c) के अंतर्गत पात्रता के मानदंड निम्न प्रकार से निर्दिष्ट थे:

(i) प्रमुख बोलीदाता का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार ₹5.00 करोड़ (लगभग) होना चाहिए।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह आवश्यक था कि प्रमुख बोलीदाता या उसका सहयोगी ने रेल वेल्डिंग संयंत्र की सफल आपूर्ति एवं स्थापना की हो। यह तर्क दिया गया कि यह शर्त अनिवार्य थी और IFB और ITB में निहित अन्य सभी प्रावधानों पर इसका अभिभावी प्रभाव था। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने उत्तरवादी क्रमांक 4 को तकनीकी एवं वाणिज्यिक बैठकों में आमंत्रित किया, याचिकाकर्ता के साथ, हालाँकि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने मानदंडों को पूरा नहीं किया|

8. अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेजों में वर्णित प्रमुख बोलीदाता की आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा नहीं किया। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने पिछले पाँच वर्षों में कम से कम 5 रेल फ़्लैश बट वेल्डिंग मशीनों के सफल निर्माणकर्ता होने की जो पात्रता निर्धारित की गई थी —— उसे पूरा नहीं किया। पैकेज B के संदर्भ में भी, उत्तरवादी क्रमांक 4 न तो प्रमुख बोलीदाता के रूप में आवश्यक व्यक्तिगत टर्नओवर की शर्तों को पूरा करता है, और न ही उसने कभी किसी अत्याधुनिक हाई–स्पीड ट्रैक प्रणाली का निर्माण या संचालन किया है, जैसा कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं में बताया गया था। अधिवक्ता ने निम्नलिखित पत्रों का उल्लेख किया P–2, दिनांक 16.06.2003, P–3, दिनांक 10.07.2003, P–4, दिनांक 10.07.2003| ये पत्र रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य (इंजीनियरिंग) को लिखे गए थे। 22.07.2003 को याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 को पत्र (अनुलग्नक पी–95) भेजा। तर्क दिया गया है कि जब याचिकाकर्ता को कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने अनुलग्नक पी–6 के रूप में एक अभ्यावेदन भारत सरकार के इस्पात मंत्री को भेजा।

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 ने उत्तरवादी क्रमांक 4 पर निविदा दस्तावेजों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को लागू करने में विफलता प्रदर्शित की। यह भी कहा गया कि उन्होंने शर्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उससे विचलित हो गए। याचिता के पारा 9 में यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 ने उत्तरवादी क्रमांक 4 तथा इसके सहयोगियों मेसर्स जीसमार फ्रांस और मेसर्स टेक्नो फैब, कोलकाता) से कुछ गारंटी प्राप्त की थीं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने 07.07.2003 को याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी क्रमांक 4 से संशोधित मूल्य निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा था। यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत मूल्य निविदा में विदेशी आपूर्ति (Euro में) तथा स्थानीय आपूर्ति —— दोनों सम्मिलित थीं। यह तर्क भी दिया गया कि जब बोली प्रतिनिधियों को मूल्य निविदाएं पढ़कर सुनाई गईं, तो यह देखा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने लगभग 40% मशीन लागत को विदेशी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के अंतर्गत दिखाया है, पैकेज A और B दोनों में, जिसका उद्देश्य था बोली मूल्यांकन के नियम ITB 38.2(c) के तहत कम शुल्क दर का लाभ उठाना। उल्लेखित नियम के अनुसार अनुसंधान एवं विकास उपकर केवल 5% लगाया जाता है, जबकि मशीन CIF मूल्य पर सामान्य कस्टम ड्यूटी 25% होती है। यह भी तर्क दिया गया कि इससे उत्तरवादी क्रमांक 4 को अनुचित लाभ प्राप्त होता। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 की मशीनें प्रमाणित डिज़ाइन (proven design) की नहीं थीं, क्योंकि उनके डिज़ाइन की लागत अत्यधिक थी। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन दोनों स्थितियों में, उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 को उत्तरवादी क्रमांक 4 की पेशकश को अस्वीकार कर देना चाहिए था, क्योंकि वे केवल प्रमाणित मशीनें ही चाहते थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कियाचिकाकर्ताओं ने अंततः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर (परियोजनाएं) और अध्यक्ष से बैठक का समय, 22.09.2003 को मांगा, परंतु वे केवल अध्यक्ष से ही मिल सके। जिन्होंने याचिकाकर्ता को कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किया।

10. अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है और उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 पैकेज A और पैकेज B के संविदा को उत्तरवादी क्रमांक 4 और उसके सहयोगियों के साथ निष्पादित करने की प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार, कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध न होने के कारण, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है, इस आधार पर कि निविदा की शर्तों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, और यह कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया दुर्भावना, अयुक्तियुक्तता और मनमानेपन पर आधारित है, इसलिए यह न्यायिक जांच के अधीन है।

11. याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों के समर्थन में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव दत्ता ने यह तर्क दिया कि प्रशासनिक कार्यवाही में भी निष्पक्षता (fair play) अपेक्षित है, और इसके समर्थन में उन्होंने रामाना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व अन्य (1979 (3) SCC 489) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रशासनिक प्राधिकरण भी उन्हीं मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के पालन के लिए बाध्य है, जिन्हें उसने दूसरों के लिए निर्धारित किया है। इन मानकों या प्रक्रियाओं की उपेक्षा उसकी कार्यवाही को अमान्य बना सकती है, जब तक कि वह कार्यवाही किसी वैध सिद्धांत पर आधारित न हो, जो कि न तो आयुक्तियुक्त हो, न ही अनुचित और न ही भेदभावपूर्ण।

12. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया जो राम और श्याम बनाम हरियाणा राज्य (AIR 1985 (3) SCC 267) में पारित हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि सरकार को सर्वोच्च बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है, और वह सर्वोच्च बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य को संविदा दे सकती है, यदि इसके लिए उचित और पर्याप्त कारण हो, जैसे कि —— सर्वोच्च बोली वास्तविक बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती या किसी कमजोर वर्ग को अवसर देने की आवश्यकता है, जो सर्वोच्च बोलीदाता से अधिक बोली लगाने में असमर्थ था। लेकिन यदि सरकार सर्वोच्च बोली को अस्वीकार करती है, तो उस पर यह बाध्यता है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे, और किसी भी स्थिति में मनमानी नहीं कर सकती। अधिवक्ता ने इस निर्णय के पैरा 11, 12 और 14 का उल्लेख किया।

13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (1991 (1) SCC 212) निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आती है, यह जाँचने के लिए कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ या नहीं, चाहे उस क्षेत्र में समीक्षा का दायरा सीमित क्यों न हो। अधिवक्ता ने इस निर्णय के पैरा 19, 22 और 24 पर भरोसा किया।

14. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया जी.बी. महाजन बनाम जलगांव नगर परिषद व अन्य (1991 (3) SCC 91 के निर्णय पर भी भरोसा किया और तर्क दिया कि यदि सरकारी संविदा से संबंधित न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसमें सार्वजनिक कानून का तत्व होना आवश्यक है। उन्होंने निर्णय के पैरा 46 का उल्लेख किया।

15. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ (1994 (6) SCC 651) के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है, न कि स्वयं निर्णय की गुणवत्ता; क्योंकि न्यायालय समीक्षा करते समय अपील न्यायालय की तरह कार्य नहीं करता जब मामला नीतिगत निर्णय से संबंधित होता है ——जैसे कि सरकार की संविदा की स्वतंत्रता, निविदा आमंत्रण, या किसी निविदा को अस्वीकार करने का निर्णय ——तो ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि निर्णय मनमाना, अनुचित, गैरकानूनी, अपारदर्शी या अति–अविवेकपूर्ण (Wednesbury's unreasonableness) न हो, यानी ऐसा निर्णय जो कोई भी विवेकशील व्यक्ति उचित सोच के साथ नहीं ले सकता या जिसमें प्रक्रियात्मक अनियमितता हो। परीक्षण का मानदंड यह है: क्या निर्णय में ऐसा कोई गंभीर दोष है जिसके कारण न्यायालय को हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है? यदि हाँ, तो न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधार सकता है, लेकिन वह विशेषज्ञों की राय के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित नहीं करेगा। न्यायिक पूर्णरविलोकन का सिद्धांत सरकारी निकायों की अनुबंधात्मक शक्तियों के उपयोग पर भी लागू होता है, ताकि मनमानेपन या पक्षपात को रोका जा सके। उन्होंने निर्णय के पैरा 70, 76 और 80 का उल्लेख किया।

16. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मोनार्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम ठाणे नगर निगम व अन्य (2000 (5) SCC 287) का हवाला दिया और तर्क दिया कि सरकारी कार्रवाई जब मनमानी या भेदभावपूर्ण हो, तो न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक होता है इस मामले में निविदा आमंत्रण ऑक्ट्रॉय वसूली एजेंटों की नियुक्ति

हेतु जारी किया गया था, जिसमें शर्तें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट थीं; उनमें से एक पात्रता शर्त निविदा प्रस्तुत करने की समयसीमा समाप्त होने के बाद, परंतु खोलने से पहले हटा दी गई। इस स्थिति में ऐसे बोलीदाता को संविदा देना, जो निविदा प्रस्तुत करते समय शर्तों को पूरा नहीं करता था, उच्च न्यायालय द्वारा मनमानी करार देते हुए सही रूप से रद्द किया गया। उन्होंने इस निर्णय के पैरा 11, 12 और 14 का उल्लेख किया।

17. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने डब्ल.बी.स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड व अन्य (2001 (2) SCC 451) के निर्णय का भी हवाला दिया। उन्होंने इस निर्णय के प्लेसिटम A, B और E का उल्लेख किया।

18. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दत्ता एसोसिएट्स बनाम इंडो मर्चन्टिलेस व अन्य (1997 (1) SCC 53) निर्णय पर भी भरोसा किया। उन्होंने इस निर्णय के पैरा 7 का उल्लेख किया।

19. श्री विजय हंसरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता (उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से) ने तर्क दिया कि यहाँ ऐसी कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता) या अतार्किकता नहीं है, जिसके आधार पर असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय की जांच केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित होती है न कि स्वयं निर्णय पर। यह कहा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ को संविदा प्रदान किया, जो कि सर्वाधिक कम मूल्य वाली निविदा थी — यह बात निर्विवाद है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता संविदा के आबंटन को गुण–दोष के आधार पर चुनौती देना चाहता है, जो कि विवादास्पद तथ्यों पर आधारित है, और जिन्हें रिट याचिका के माध्यम से न्यायालय में नहीं सुलझाया जा सकता। रिट याचिका विलंब का सिद्धांत (principle of delay) के अधीन भी बाधित है। निविदाएं 07.05.2003 को खोली गई थीं। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता पर आपत्ति उठाई थी अपने दिनांक 16.06.2003 के प्रतिनिधित्व पत्र के माध्यम से — परंतु वही अस्वीकृत कर दिया गया था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ — दोनों ने संशोधित मूल्य निविदाएं (revised bids) प्रस्तुत की थीं, जो कि 07.07.2003 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोली गईं और उस समय याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं की। इसके पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेंट दिनांक 21.08.2003 को जारी किया गया, और औपचारिक संविदा 21.09.2003 को निष्पादित किया गया। यह सभी तथ्य याचिकाकर्ता को भलीभांति ज्ञात थे।

20. अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यह याचिका विबंधन और स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पूरा संविदा आवंटन प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ — दोनों पर विचार किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लिया, इसलिए वह अब उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता को चुनौती देने से रोका गया है।

21. उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अखबार में निविदा का प्रकाशन दिनांक 5/8.6.2002 को किया गया था। प्रकाशन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उत्तरवादी किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, बिना कोई कारण बताए। इसके लिए बोलीदाताओं के लिए निर्देश के खंड 42.1 का उल्लेख किया गया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उचित विचार–विमर्श के पश्चात समिति ने यह निर्णय लिया कि रेल वेल्डिंग संयंत्र पैकेज को उपयुक्त उप–पैकेजों में विभाजित कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाए। प्रत्येक उप–पैकेज के लिए तकनीकी विशिष्टताओं को निर्धारित करने का कार्य सेण्टर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को सौंपा गया।

22. श्री हंसरिया ने तर्क प्रस्तुत किया कि बोलीदाताओं के लिए निर्देश के खंड 8.3 के अनुसार, दो या अधिक पक्षों का संघ भी बोली प्रस्तुत कर सकता है। जहां तक पात्रता का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि — संघ को पात्रता प्राप्त करने के लिए, इसके प्रत्येक सदस्य या उनके किसी भी संयोजन को न्यूनतम मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य था। निविदा दस्तावेजों में जो पात्रता मानदंड निर्दिष्ट थे, वे व्यक्तिगत बोलीदाता के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। सामान्य संविदा शर्तों के खंड 11.4 में "ठेकेदार" की परिभाषा दी गई है, जिसमें एक या एक से अधिक संघ सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। खंड 3.9.1 के अनुसार, जहां ठेकेदार कोई संघ है, वहां संघ के सभी सदस्य संविदा की पूर्ति हेतु नियोक्ता के प्रति संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

23. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 — दोनों ने निविदा दस्तावेजों का अनुरोध किया, जो उन्हें उपलब्ध कराए गए। निविदाएं केवल दो पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गईं — याचिकाकर्ता, और एक संघ, जिसमें सम्मिलित थे उत्तरवादी क्रमांक 4,मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस, और बाद में शामिल हुआ —

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, मुंबई (पैकेज A के लिए)। पैकेज B के लिए संघ में सम्मिलित थे उत्तरवादी क्रमांक 4, मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस, मेसर्स टेक्नो फैब मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., कोलकाता, और बाद में शामिल हुआ —— मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, मुंबई। अधिवक्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 के अग्रेषण पत्र दिनांक 02.05.2003 का उल्लेख किया, जो पैकेज A से संबंधित था, तथा पैकेज B के लिए भी उत्तरवादी क्रमांक 4 का अग्रेषण पत्र दिनांक 02.05.2003 संलग्न था।

24. अधिवक्ता ने आगे कहा कि बोली दस्तावेजों के साथ, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने संघ के सदस्यों के बीच समझौता ज्ञापन संलग्न किया था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। संघ के एक सदस्य —— मेसर्स एल. जीस्मार —— ने पाँच स्वचालित फ़्लैश बट वेल्डिंग मशीनों की सफल आपूर्ति एवं स्थापना की है। पिछले तीन वर्षों में पाँच स्वचालित फ़्लैश बट रेल वेल्डिंग मशीनों की आपूर्ति की गई थी, जबकि पात्रता की आवश्यकता यह थी कि यह कार्य पिछले पाँच वर्षों में किया गया हो। जहाँ तक पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार की आवश्यकता का प्रश्न है, यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 स्वयं ₹6.00 करोड़ का औसत टर्नओवर रखता है।

25. अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि दुनिया भर में केवल चार पक्ष उपलब्ध हैं, जो आधुनिक रेल वेल्डिंग मशीनों के निर्माता/आपूर्तिकर्ता हैं, जिसमें याचिकाकर्ता और मेसर्स जीस्मार, फ्रांस (जो कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का संघ सदस्य है) सम्मिलित हैं। समिति ने यह विचार किया कि मेसर्स जीस्मार, फ्रांस, जो कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का संघ सदस्य है, पिछले पाँच वर्षों में पाँच मशीनों की आपूर्ति की पात्रता को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, दुनिया भर के चार निर्माताओं में से एक वर्तमान में इस व्यापार में सक्रिय नहीं है, दूसरा पक्ष बोली में सम्मिलित नहीं हुआ,और यदि उत्तरवादी क्रमांक 4 का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होता, तो: (a) उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास केवल एक ही पक्ष —— अर्थात याचिकाकर्ता —— शेष रह जाता, जिससे वही स्थिति उत्पन्न होती जो पुनः निविदा से पहले थी; (b) यह मूल्य में कमी प्राप्त करने और एकल पक्ष के साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अत्यंत कठिन होता; (c) कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, और पुनः निविदा आमंत्रित करने का उद्देश्य —— स्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करना —— पूरा नहीं हो पाता।

High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस अवस्था में निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकते थे...

{i} वैश्विक निविदा प्रक्रिया, तकनीकी–वाणिज्यिक जांच/चर्चा आदि की संपूर्ण प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली है, जिससे रेल वेल्डिंग संयंत्र की कुल कमीशनिंग अनुसूची में और अधिक विलंब होता, जो अंततः काफी लागत वृद्धि का कारण बनता।
{ii} रेल वेल्डिंग संयंत्र के अन्य पैकेज आपूर्तिकर्ता भी अपने पैकेज की कमीशनिंग में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते थे।
{iii} चूंकि इस क्षेत्र में पक्ष सीमित हैं, इसलिए बार–बार पुनः निविदा) करने से कम प्रतिक्रिया की संभावना से बचा नहीं जा सकता था।

26. अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि मूल्य निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट को निविदा समिति को सौंपा गया, और उत्तरवादी क्रमांक 4 की निविदा को पैकेज A और पैकेज B दोनों के लिए स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 21.08.2003 को, पैकेज A और पैकेज B दोनों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए, तथा दिनांक 21.09.2003 को, दोनों परियोजनाओं के लिए औपचारिक अनुबंधों पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए और उन्हें निष्पादित किया गया, जो कि उत्तरवादी क्रमांक 3 और उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ के सदस्यों के बीच संपन्न हुए।

27. अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अनुबंधों के हस्ताक्षर के बाद, परियोजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु कई बैठकें आयोजित की गईं। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी संघ के सभी सदस्यों द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जा चुकी है।

28. श्री हंसरिया ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने पैकेज A के लिए अपने तथा अपने संघ के सदस्यों मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस की ओर से की बोली प्रस्तुत किया था। पैकेज B के लिए उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा, इसके स्वयं के, तथा इसके संघ सदस्य —— मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस और मेसर्स टी.एफ.एम. लिमिटेड, कोलकाता की ओर से बोली प्रस्तुत किया गया था।

29. श्री हंसरिया ने याचिका के पैरा 10 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका सद्भावनापूर्ण आशय से नहीं दायर की है। पैरा 10 में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि उन्हें यह जानकारी प्राप्त

हुई है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने 20 अगस्त, 2003 के आसपास उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है, तथा वे पैकेज A और पैकेज B के लिए संविदा, उत्तरवादी क्रमांक 4 और उसके सहयोगियों के साथ निष्पादित करने की प्रक्रिया में हैं। विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य याचिका के प्रार्थना खंड (b) और (c) का उल्लेख किया।

30. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरी याचिका में संविदा को निरस्त करने का कोई स्पष्ट अनुरोध नहीं किया गया है, यह केवल स्थगन आवेदन के प्रार्थना खंड (a) में संक्षेप में उल्लेखित है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास है। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य याचिका में ऐसा कोई स्पष्ट प्रार्थना खंड नहीं है, जिसमें संविदा को निरस्त करने की मांग की गई हो। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिका दाखिल करने में देरी की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि: निविदाएं 07.05.2003 को खोली गईं, उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा 16.06.2003 को आपत्ति दर्ज की गई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, इसके बाद याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 का संघ —दोनों ने संशोधित निविदाएं प्रस्तुत कीं, जो कि 07.07.2003 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोली गईं। यह कहा गया कि पक्षकारों की उपस्थिति में मूल्य निविदाएं खोली गईं, लेटर ऑफ इंटेंट दिनांक 21.08.2003 को उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में जारी किया गया, तथा दिनांक 21.09.2003 को उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ के साथ औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। यह तर्क दिया गया कि इन सभी तथ्यों की जानकारी याचिकाकर्ता को पूर्ण रूप से थी,फिर भी वर्तमान याचिका 01.11.2003 को दायर की गई, इन तथ्यों को छुपाते हुए। यह प्रस्तुत किया गया कि यह याचिका विलंब से दायर की गई है और प्रक्रियात्मक देरी से ग्रसित है।

31. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ (1994 (6) SCC 651) पर भरोसा किया। उन्होंने निर्णय के अनुच्छेद 70, 71, 77, 81 और 94 का उल्लेख किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

32. अधिवक्ता ने रौनक इंटरनेशनल बनाम आई वी आर कंस्ट्रक्शन(1991 (1) SCC 492) के निर्णय पर भी भरोसा किया और निर्णय के पैरा 11 और 12 का हवाला दिया।

33. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के अधिवक्ता ने एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2000 (2) SCC 617) के निर्णय का उल्लेख किया और पैरा 7 पर भरोसा किया।

34.अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि संघ कंपनियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी उद्यम में संयुक्त या सहयोगी रूप से सम्मिलित होता है। उन्होंने इस विषय में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने न्यू हॉरिज़ोन्स बनाम भारत संघ (1995 (1) SCC 478) में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और निर्णय के पैरा 23 का उल्लेख किया |

35. विद्वान वकील ने रामाना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व अन्य (AIR 1979 SC 1628) के निर्णय पर भी भरोसा किया और पैरा 34 का उल्लेख किया। उन्होंने आगे जी.बी. महाजन बनाम जलगांव नगर परिषद व अन्य (1991 (3) SCC 91) के निर्णय पर भी भरोसा किया और पैरा 46 का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने आगे गुजरात राज्य बनाम मेघजी (1994 (3) SCC 552) के निर्णय का भी उल्लेख किया और पैरा 22 पर भरोसा किया। उन्होंने केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम कुरियन (2000 (6) SCC 293) के निर्णय का भी हवाला दिया और पैरा 10 का उल्लेख किया। उन्होंने कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन्स बनाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (2002 (8) SCC 177) के निर्णय पर भी भरोसा किया और पैरा 10 का उल्लेख किया।

36. श्री रविंद्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित हुए और कहा कि वह उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस — उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ का सदस्य है। उत्तरवादी क्रमांक 4 और उसके संघ का सदस्य मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस, वर्षों से दुनिया भर में रेल जॉइनिंग एप्लिकेशन के लिए स्केलेटर ब्रांड की वेल्डिंग मशीनों की आपूर्ति करता रहा है। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपनी ओर से तथा मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस की ओर से पैकेज A के लिए, और मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस एवं मेसर्स टेक्नोफैब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कोलकाता की ओर से पैकेज B के लिए बोली प्रस्तुत की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया कि याचिकाकर्ता "सत्य का गोपन" और "असत्य का सुझाव" का दोषी है। यह तर्क दिया गया कि पूरी याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केवल पैकेज A के लिए पात्रता की शर्तों को चुनौती दी गई है, जिसमें केवल पैकेज A संविदा की शर्तें, योग्यता और प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जबकि "A" और "B" दोनों पैकेज भिन्न हैं। वरिष्ठ

अधिवक्ता ने विशेष रूप से यह जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में आने में देरी की है, साथ ही उसने अधित्यजन और सहमति दर्शाई है।

37. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निविदा की शर्तों के अनुसार, विशेष रूप से खंड 8.3 में यह स्पष्ट है कि यदि कोई संघ बोली प्रस्तुत करता है, तो संघ के प्रत्येक सदस्य या उनके किसी भी संयोजन को ITB क्लॉज–I के अनुसार उस संविदा घटक के लिए आवश्यक सभी मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है, जिसके निष्पादन के लिए वे नामित किए गए हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि ठेकेदार दो या अधिक पक्षों का संघ है, तो ऐसे सभी पक्ष संविदा की शर्तों को पूरा करने हेतु नियोक्ता के प्रति संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। और ऐसे पक्षों में से किसी एक को नेता के रूप में नामित किया जाएगा, जिसे पूरे संघ को बाध्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

38. अधिवक्ता ने अनुलग्नक R/4(4) और R/4(5) का भी उल्लेख किया, जो कि बोलीदाताओं के लिए निर्देश और संविदा की सामान्य शर्तों से संबंधित हैं। तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि संघ द्वारा बोली प्रस्तुत करने के मामलों में, संघ का प्रत्येक सदस्य प्रमुख बोलीदाता माना जाता है। अतः संघ के संदर्भ में बोलीदाता की पात्रता और योग्यता का तात्पर्य है सदस्यों के समूह के सम्मिलन की पात्रता और योग्यता। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4, मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस के साथ मिलकर पैकेज A के सभी पक्षों में पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। जहाँ तक पैकेज B का संबंध है, उत्तरवादी क्रमांक 4 सभी आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। यह दोहराया गया कि संघ के एक सदस्य —— मेसर्स एल. जीस्मार, फ्रांस —— ने पिछले तीन वर्षों में पाँच ऑटोमैटिक फ़्लैश बट रेल वेल्डिंग मशीनों की आपूर्ति और कमीशनिंग सफलतापूर्वक की है,पिछले पाँच वर्षों में ऐसा कार्य करने की जब भी आवशयकता पड़ी थी।

39. अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि बहस बिना पर्याप्त याचिकात्मक आधार के प्रस्तुत की गई है। श्री श्रीवास्तव ने अनुलग्नक P/2 के पैरा 1 का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

"आपके पत्रों के अनुसार, हमारे प्रतिनिधि और इस कार्य हेतु सहयोगी हैं ——मेसर्स अडवाणी ओरलिकॉन लिमिटेड ने पैकेज A और B के लिए हमारी पेशकश से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक बैठकों में भाग लिया, जो 2.5.2003 से 6.6.2003 तक भिलाई में आयोजित की गई थीं। हमें आशा है कि हम इस बैठक के उद्देश्यों की पूर्ति में आपकी सहायता कर पाए होंगे, और आपके पत्रों में उठाए गए प्रश्नों को स्पष्टता से समझाने और उत्तर देने में सहायक रहे होंगे।"

40. वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे याचिका के पैरा 9 (m), (n), (p), (q), (r) और (u) का उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से पैरा 9(o) की ओर ध्यान आकर्षित किया। पैरा 9(o) का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"(o)... ... यह इंगित किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4, जो कि प्रमुख बोलीदाता और संघ का नेता था, और मेसर्स जीस्मार – फ्रांस को अस्वीकृत कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास आवश्यक अनुभव, संदर्भ और वार्षिक कारोबार नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने पहली बार यह आरोप लगाया कि दूसरी बार निविदा आमंत्रित करने का कारण सिर्फ उत्तरवादी क्रमांक 4 को लाभ पहुंचाना था। चूंकि यह पहली बार था कि भारतीय रेलवे और सेल तेज़ गति की रेलगाड़ियों के लिए आधुनिक उच्च तकनीक वेल्डेड स्टील रेल ट्रैक का चयन करने जा रहे थे, इसलिए आवश्यक था कि वे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे किफायती समाधान चुनते, जैसा कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।"

यह इंगित किया गया कि इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत निविदा एक संघ के रूप में थी, केवल उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा अकेले नहीं।

41. विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत उत्तर के पृष्ठ 30 और 31 में वर्णित "एल. जीस्मार की बिक्री संदर्भ सूची" का उल्लेख किया। यह दर्शाया गया कि निविदा संघ के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, और उसी रूप में स्वीकार की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि 2/5/2003 को निविदा संघ द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कि पृष्ठ 24 से 36 तक के दस्तावेजों में वर्णित है। इस चरण पर अधिवक्ता ने याचिका के पैरा 9(m) का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि यह सार्वजनिक जानकारी थी और यह भी कि निविदा के खुलने के विवरण से यह स्पष्ट था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि यह जानकारी सामान्य रूप से उपलब्ध थी, तो याचिकाकर्ता ने इतनी देर तक प्रतीक्षा क्यों की? यह भी कहा गया कि केवल तब जब सारे दस्तावेज सामने आ गए और तकनीकी तथा वाणिज्यिक मुद्दों पर बैठकों का आयोजन 7/7/2003 को हुआ, तभी याचिकाकर्ता ने हंगामा खड़ा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि 10/7/2003 को याचिकाकर्ता ने आपत्ति उठाई, जबकि यह बात 7/7/2003 को स्पष्ट हो गई थी कि उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ द्वारा प्रस्तुत संशोधित मूल्य याचिकाकर्ता की

तुलना में कम था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पृष्ठ 46 पर उपलब्ध दस्तावेज़ का उल्लेख किया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 7/5/2003 से लेकर 1/11/2003 तक की अवधि में, याचिकाकर्ता ने भागीदारी की, उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ को अनुमति दी, बैठकों को होने दिया, तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन पूरा हुआ, संविदा 21/9/2003 को निष्पादित हुआ, ₹12.93 करोड़ की बैंक गारंटी पैकेज A के लिए प्रस्तुत की गई, और ₹18.73 करोड़ की बैंक गारंटी पैकेज B के लिए प्रस्तुत की गई, लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया, ले–आउट और ड्रॉइंग पूरी हुई, बेसिक इंजीनियरिंग कार्य हो चुका था, और इन सभी कार्यों में याचिकाकर्ता की मूक स्वीकृति रही। इसलिए यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता "स्वीकृति" और "प्रक्रियात्मक देरी" के आधार पर किसी राहत का हकदार नहीं है।

42. वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम बलवंत रेगुलर मोटर सर्विस (AIR 1969 SC 329) पर भरोसा किया। उन्होंने निर्णय के पैरा 15 का उल्लेख किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि केवल प्रतिवेदन लिखने मात्र से देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता, और न ही इससे स्वीकृति और अधित्यजन से मुक्ति मिलती है। उन्होंने आगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जगदीश नारायण मल्तियार बनाम बिहार राज्य (AIR 1973 SC 1343) का उल्लेख किया, और पैरा 8 को उद्धृत किया। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता ने सामंता एवं अन्य बनाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (2001 (5) SCC 323) का उल्लेख किया, और पैरा 9 को उद्धृत किया। उन्होंने सुनिता अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य (2000 (2) SCC 615) के निर्णय का भी हवाला दिया, और पैरा 4 का उल्लेख किया।

43. वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि "संयुक्त व्यवहार" में कुछ लचीलापन स्वाभाविक होता है। इसके लिए उन्होंने राजबिहारी पांडा बनाम उड़ीसा राज्य (AIR 1969 SC 1081) के निर्णय का हवाला दिया, और पैरा 17 को उद्धृत किया। उन्होंने आगे हंसराज केहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (AIR 1975 SC 389) के निर्णय का भी उल्लेख किया, और पैरा 8 का हवाला दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जैसवाल एवं अन्य (AIR 1987 SC 251) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। उन्होंने आगे न्यू हॉरिज़ोन्स बनाम भारत संघ (AIR 1995 (1) SCC 478) के निर्णय पर भी भरोसा किया और पैरा 3, 6, 17, 18, 23 और 26 का उल्लेख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने रौनक इंटरनेशनल बनाम आई वी आर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (1991 (1) SCC 492) के निर्णय का भी उल्लेख किया और पैरा 8, 9, 10 और 11 का हवाला दिया।

44. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 एक भारतीय कंपनी है और उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने का अधिकार प्राप्त है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कंपनी का एक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A(j) के तहत निर्धारित है, जो यह कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करे, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर के प्रयास और उपलब्धि की ओर अग्रसर हो।

45. उत्तर देते हुए, श्री राजीव दत्ता, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोहराया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहाँ न तो स्वीकृति (acquiescence) है, न त्याग (waiver), और न ही विलंब। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरवादी क्रमांक 4 को आवश्यक पक्ष के रूप में याचिका में सम्मिलित किया गया है, और वह अन्य पक्षों का भी प्रतिनिधित्व करता है।

46. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक एवं विधिक तर्कों को जहाँ तक संभव हुआ है, ऊपर उल्लिखित किया गया है, और उनका विचार किया जा रहा है। याचिका में जो प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे, उनके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कानूनी और तथ्यात्मक तर्कों की चर्चा की जा चुकी है।

47. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. विनोद कुमार बनाम एस. पलानीसामी एवं अन्य [2003 (10) SCC 681] के निर्णय में यह माना है कि — प्रशासनिक मामलों में लिए गए निर्णयों एवं कार्यवाहियों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा केवल निर्णय–लेने की प्रक्रिया तक सीमित होता है, न कि निर्णय के गुण–दोष तक। यह विधि के अंतर्गत स्थिर रूप से मान्य है कि — केवल निर्णय–लेने की प्रक्रिया ही पुनरीक्षित हो सकती है, न कि स्वयं निर्णय की गुणवत्ता, क्योंकि न्यायालय, पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता। किसी निर्णय या कार्रवाई को पूर्णरविलोकन के लिए तभी खोला जा सकता है, यदि यह प्रमाणित किया जाए कि — निर्णय मनमाना, अनुचित, अवैध, अतार्किक है, या उसमें "वेडनसबरी अविवेक" निहित है अर्थात ऐसा निर्णय जिसे कोई विवेकशील व्यक्ति उचित सोच के साथ नहीं ले सकता, या जिसमें प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हों। इसका अंतिम परीक्षण यह है कि — क्या त्रुटि इतनी गंभीर है कि न्यायालय का हस्तक्षेप

आवश्यक हो जाता है? यह विधिक रूप से स्थिर सिद्धांत है कि —न्यायालय विशेषज्ञों की राय के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। टाटा सेलुलर (पुर्वित) मामले में आगे यह भी निर्णय लिया गया कि सिर्फ चयन करने की शक्ति को मनमानी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि न्यायालय द्वारा माना गया और प्रस्तुत किया गया — न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत सरकारी निकायों द्वारा अनुबंधात्मक शक्तियों के प्रयोग पर भी लागू होते हैं, ताकि मनमानेपन या पक्षपात को रोका जा सके। हालाँकि, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। सरकार राज्य की वित्तीय संसाधनों की संरक्षक होती है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा करे। सरकार को हमेशा यह अधिकार होता है कि वह न्यूनतम बोली या किसी भी अन्य बोली को अस्वीकार कर सकती है। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करते समय आवश्यक है। यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या सर्वोत्तम कोटेशन प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चयन करने का अधिकार अपने आप में मनमाना नहीं माना जा सकता। हालाँकि, यदि यह शक्ति किसी गौण या सांपर्शविक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाए, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रशासनिक मामलों में न्यायिक जांच का उद्देश्य प्रशासनिक विवेकाधिकार और अनुचितता के बीच संतुलन स्थापित करना रहा है — चाहे वह निर्णय अनुबंधात्मक, राजनीतिक या सामाजिक नीति से संबंधित हो — जो कि आवश्यक रूप से न्यायालय में विवाद के योग्य नहीं होते, लेकिन फिर भी, यदि कोई असंगत या अनुचित व्यवहार होता है, तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा सुधारा जा सकता है।

48. सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सेलुलर (पुर्वित) में पाँच शर्तों को निर्धारित किया है। इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह जांचे कि क्या वे सभी शर्तें पूरी की गई हैं या नहीं। न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्णयकर्ता द्वारा तथ्यों के मूल्यांकन की समीक्षा करे। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब संपूर्ण तथ्यों को देखने के पश्चात उस निष्कर्ष पर पहुँचना तार्किक न हो, जो निर्णयकर्ता ने निकाला हो। यदि किसी विशेष कार्यवाही की ओर संकेत करने वाले तथ्यों का भार अत्यधिक हो, और फिर भी निर्णय विपरीत दिशा में लिया गया हो, तो ऐसा निर्णय स्थिर नहीं रह सकता। एक निर्णय तब अविवेकपूर्ण माना जाएगा, जब वह पक्षपातपूर्ण हो या विभिन्न वर्गों के बीच असमान रूप से कार्य करे। इस संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए गए हैं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(1) आधुनिक प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि प्रशासनिक कार्यवाहियों में न्यायिक संयम अपनाया जाना चाहिए।

(2) न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि केवल यह समीक्षा करता है कि निर्णय किस प्रकार लिया गया।

(3) न्यायालय के पास यह विशेषज्ञता नहीं होती कि वह प्रशासनिक निर्णय को सुधार सके। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाए, तो न्यायालय अपनी राय प्रतिस्थापित कर देगा, जो स्वयं ग़लत हो सकती है, क्योंकि उसके पास आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होती।

(4) निविदा आमंत्रण की शर्तों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह संविदा के क्षेत्र में आता है। सामान्यत: संविदा देने का निर्णय कई चरणों की बातचीत के माध्यम से लिया जाता है, और प्रायः ऐसे निर्णय गुणात्मक रूप से विशेषज्ञों द्वारा लिए जाते हैं।

(5) सरकार को संविदा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक कार्यों या अर्ध–प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे निकाय के लिए "निष्पक्षता" आवश्यक है। हालाँकि, ऐसे निर्णयों को वेडनसबरी के विवेक सिद्धांत तथा अन्य पहलुओं के आधार पर परखा जाना चाहिए, और वे निर्णय पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी से मुक्त होने चाहिए। ऐसे निर्णयों को निरस्त करना प्रशासन पर भारी बोझ डाल सकता है और इससे बजट से बाहर का खर्च बढ़ सकता है।

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि न्यायिक पूर्णरविलोकन की शक्ति का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कार्यपालिका की असीमित शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। इस नियंत्रण की दो प्रमुख रूपें होती हैं: एक, न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा, और दूसरी, न्यायालय की उस सीमा को दर्शाती है जिसमें वह किसी प्रशासनिक निर्णय को उसके गुण–दोष पर रद्द कर सकता है। ये नियंत्रण प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण की विशेषता हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य उस निर्णय के गुण–दोष की समीक्षा करना नहीं है, जिसके समर्थन में पुनर्विलोकन की याचिका दायर की गई है, बल्कि यह जांचना है कि निर्णय–लेने की प्रक्रिया उचित थी या नहीं। इस प्रकार, यह अपील से भिन्न है। जब अपील की सुनवाई की जाती है, तो न्यायालय उस निर्णय के गुण–दोष पर विचार करता है। चूंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अपील नहीं होती, इसलिए न्यायालय अपने

निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, न्यायालय इसके लिए सक्षम भी नहीं होता, और ऐसा करना वांछनीय भी नहीं माना जाता। जहाँ चयन या अस्वीकृति मनमाने ढंग से की गई हो, न्यायालय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। न्यायाधीश का कार्य यह नहीं है कि वह एक सुपर बोर्ड की तरह कार्य करे, या किसी कठोर शिक्षक की तरह अत्यधिक तकनीकी उत्साह में आकर प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय का स्थान ले ले।

50. टाटा सेलुलर (पूर्वत) मामले में आगे यह भी निर्णय हुआ कि न्यायालय का कर्तव्य केवल "वैधानिकता" तक सीमित होता है। न्यायालय को केवल निम्न प्रश्नों पर विचार करना चाहिए:

1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है?
2. क्या कोई कानूनी त्रुटि हुई है?
3. क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है?
4. क्या ऐसा निर्णय लिया गया है जिसे कोई विवेकशील न्यायाधिकरण कभी नहीं लेता?
5. क्या अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है?

   इसलिए, यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह यह निर्धारित करे कि कोई विशेष नीति या उस नीति की पूर्ति में लिया गया निर्णय उचित है या नहीं। न्यायालय केवल यह देखेगा कि वह निर्णय किस प्रकार लिया गया। निष्पक्ष ढंग से कार्य करने का दायित्व प्रत्येक मामले में अलग–अलग हो सकता है। प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक पुनर्विलोकन का नियंत्रण निम्न वर्गों में किया जा सकता है:

(i) अवैधता : निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसके निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है, और उसे उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

(ii) अतार्किकता: जिसे वेडनसबरी अयुक्तियुक्तता कहा जाता है। यह तब लागू होता है जब कोई निर्णय तर्क और नैतिक मानकों के इतने विपरीत होता है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति, जिसने उस मुद्दे पर विचार किया हो, ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। यह वह स्थिति है जहां कोई प्राधिकारी, जो प्रासंगिक कानून को समझता हो और तर्कसंगत रूप से कार्य कर रहा हो, फिर भी ऐसा निर्णय न ले।

(iii) प्रक्रियात्मक त्रुटि: जहाँ तय की गई प्रक्रिया का उल्लंघन होता है।

51. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार (2003 (4) SCC 579) के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों पर विचार किया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16 में। इस निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों पर चर्चा की है जो समय–समय पर न्यायालयों द्वारा स्थापित किए गए हैं। एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड बनाम वेड्रेस्बुरी कारपोरेश (K.B. p. 230 : All ER p. 683 F–G) के निर्णय में लॉर्ड ग्रीनी द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध अंश इस प्रकार है:

"यह साबित किया जाना चाहिए कि निर्णय इस हद तक अविवेकपूर्ण है कि न्यायालय उसे ऐसा निर्णय मानता है जिसे कोई विवेकशील संस्था कभी नहीं ले सकती। यह यह नहीं है कि न्यायालय किसे अविवेकपूर्ण मानता है... इस कानून का प्रभाव यह नहीं है कि न्यायालय को एक विचार की शुद्धता का निर्णायक बना दिया जाए।"

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्वत) के निर्णय का पैरा 18 भी प्रासंगिक है और निम्नलिखित है:

"18. इसलिए, युक्तियुमतता पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या प्रशासक ने प्रासंगिक कारकों को नजरअंदाज कर दिया है या अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया है।
प्रशासक का निर्णय कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय जो कोई समझदार व्यक्ति, उपरोक्त सिद्धांतों को देखते हुए, ले ही न सके। निर्णय सद्भावपूर्ण होना चाहिए। ऐसा निर्णय कई विकल्पों में से कोई एक हो सकता है, परंतु उस विकल्प का चयन करना प्रशासनिक प्राधिकारी का अधिकार है, न कि न्यायालय का कि वह अपनी राय प्रतिस्थापित करे।"

उपरोक्त निर्णय के पैरा 20 का भी उद्धरण नीचे दिया गया है:

“20. दूसरे शब्दों में, यदि किसी निर्णय को ‘अतार्किक’ कहा जाना है, तो न्यायालय को यह घोषित करना होगा कि वह निर्णय इतना असाधारण है कि वह तर्क या नैतिक मानकों की पूर्ण अवहेलना करता है। प्रशासनिक विधि में अनुरूपता की अवधारणा को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया।”

52. रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

“यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ बोर्ड के किसी भी सदस्य के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया गया हो। न ही किसी प्रकार की गौण या परोक्ष प्रेरणा का कोई आरोप है।” यह तर्क दिया गया कि संविदा को याचिकाकर्ता को प्रदान किए जाने के विरुद्ध एकमात्र आपत्ति यह थी कि वह पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता था।

53. न्यू हॉरिज़ोन्स लिमिटेड (उपर्युक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बलपूर्वक कहा कि राज्य जब संविदा में प्रवेश करता है, तो वह एक निजी व्यक्ति की तरह नहीं होता, जो किसी भी व्यक्ति से संविदा करने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य का कार्य संविदा प्रदान करने के मामले में इस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। किसी व्यक्ति को संविदा प्रदान करने के लिए चयन का विवेक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह कार्य ऐसे मानकों या मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए जो कि मनमाने, अतार्किक या अप्रासंगिक न हों। हालांकि, यह भी मान्यता दी गई कि प्रशासनिक निकाय के लिए “स्वतंत्रता की कुछ सीमा” का होना आवश्यक है, जो कि प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हो।

54. उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नप्रकार से अभिनिर्धारित किया है:

“भले ही यह माना जाए कि 22.04.1993 की निविदा आमंत्रण अधिसूचना में उल्लिखित अनुभव की शर्त केवल योग्यता के मूल्यांकन की एक पूर्वशर्त है, यद्यपि इसके लिए हमें कोई आधार नहीं मिला, तथापि यह अनुभव की आवश्यकता इस प्रकार व्याख्यायित नहीं की जा सकती कि वह अनुभव केवल उसी निविदाकार के नाम से होना चाहिए। यह ऐसी स्थिति की कल्पना करना संभव है जिसमें कोई व्यक्ति, जिसके पास पूर्व अनुभव हो, उसने किसी साझेदारी में प्रवेश किया हो, और निविदा उस साझेदारी फर्म के नाम पर प्रस्तुत की गई हो, जिसके पास पूर्व अनुभव न भी हो। अनुभव का कंपनी के अपने नाम पर होना अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि फर्म के किसी भागीदार के पिछले अनुभव को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसी प्रकार, कोई कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित है और जिसके पास पूर्व अनुभव है, वह यदि किसी अन्य कंपनी के साथ विलय या समामेलन के परिणामस्वरूप पुनर्गठित हो जाए — जिसके पास ऐसा कोई अनुभव न हो — और निविदा पुनर्गठित कंपनी के नाम से प्रस्तुत की जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मूल कंपनी का अनुभव मान्य नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि निविदा उसके नाम पर नहीं, बल्कि पुनर्गठित कंपनी के नाम पर दी गई है। इसके विपरीत, यदि कोई कंपनी विभाजित हो जाती है और कंपनी के व्यवसाय के किसी विशेष क्षेत्र को देखने वाले व्यक्ति नई कंपनी बनाकर अलग हो जाते हैं, तो ऐसी नई कंपनी के पास भले ही अपने नाम पर कोई अनुभव न हो, लेकिन उसके पास क्षेत्र विशेष में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जबकि मूल कंपनी के पास अपने नाम पर अनुभव हो सकता है, परंतु उसमें ऐसे अनुभवी व्यक्ति नहीं होते। इस स्थिति में, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उस कंपनी की पेशकश पर विचार किया जाए जिसके पास अपने नाम पर अनुभव है, जबकि उसके पास उस कार्य को करने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं; और दूसरी ओर, उस नई कंपनी की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया जाए, जिसके पास नाम पर अनुभव नहीं है, परंतु उसमें अनुभव रखने वाले व्यक्ति कार्यरत हैं। जब अनुभव की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह आवश्यकता एक व्यावसायिक लेन–देन के लिए आमंत्रण–पत्र में निहित है। ऐसे दस्तावेज की शर्तों और प्रावधानों की व्याख्या एक समझदार व्यवसायी के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। जब कोई व्यवसायी कोई संविदा करता है, जिसके अंतर्गत कोई कार्य निष्पादित किया जाना है, तो वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस व्यक्ति को वह कार्य सौंप रहा है, उसकी साख क्या है। ऐसी साख का मूल्यांकन व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है — जिसका अर्थ है कि यदि संविदा किसी कंपनी के साथ किया जा रहा है, तो वह कंपनी की पृष्ठभूमि और उसके नियंत्रण में कार्यरत व्यक्तियों तथा उनके कार्य निष्पादन की क्षमता की जांच करेगा। कंपनी के नाम से नहीं बल्कि वह उसके पीछे कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता से मूल्यांकन किया जाता है।”

55.यह सुस्थापित है कि सरकार या उसके अधीन संस्थान किसी परियोजना के प्रबंधन हेतु कोई भी विधि या तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जब तक कि वह संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं है। सरकार या उसकी संस्थाएँ परियोजना के निष्पादन हेतु कोई भी विधि विकसित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब तक वह विधि संविधान और कानून की सीमाओं में है, तब तक

न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र खुला नहीं होता। सरकारी अनुबंधों के मामलों में, सार्वजनिक विधिक तत्व का होना आवश्यक है ताकि न्यायिक पुनर्विलोकन का आह्वान किया जा सके।

56. सर्वोच्च न्यायालय ने जी बी महाजन (पूर्वत) मामले में यह निर्णय दिया:

"राज्य की व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में उपस्थिति के विस्तार और सरकारी आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की विविधता के साथ, सरकार की यह चिंता बढ़ती जा रही है कि दक्षता को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, लागत को कम कैसे किया जाए, प्रबंधन की विधियों को कैसे सुधारा जाए, परियोजनाओं में समय और लागत की अति से कैसे बचा जाए, लागत और समय का संतुलन कैसे हो, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत–लाभ अनुपात इत्यादि कैसे सुनिश्चित किए जाएं। इन मूल्यों की खोज में, परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु उचित तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो सकता है, जिनमें आर्थिक व्यवहार्यता जुड़ी होती है। ये सभी विषय आर्थिक नीति से संबंधित हैं और इन पर न्यायिक निर्णय नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वे न तो संवैधानिक या विधिक सीमाओं का उल्लंघन करते हों, न ही उनके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हों, और न ही वे स्पष्ट रूप से शक्ति का दुरुपयोग हों। यह न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक तंत्र को 'त्रुटि करने और सुधार करने' का न्यायिक स्वीकृति प्रदान करना है, बशर्ते कि वह त्रुटि और प्रयास सद्भावनापूर्ण और प्राधिकरण की सीमा के भीतर हों।" यहाँ न्यायमूर्ति ब्रैंडिस के स्मरणीय शब्दों का उल्लेख किया गया:

"भौतिक विज्ञान में खोजें और आविष्कारों में विजय यह प्रमाणित करती हैं कि 'परीक्षण और त्रुटि' की प्रक्रिया अत्यंत मूल्यवान है। इन उन्नतियों का एक बड़ा हिस्सा प्रयोग के कारण ही संभव हुआ है... "

"राज्य और राष्ट्र को यह शक्ति होनी चाहिए कि वे प्रयोगों के माध्यम से हमारी आर्थिक प्रथाओं और संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः ढाल सकें... "

"सामाजिक और आर्थिक मामलों में प्रयोग को रोकना एक गंभीर उत्तरदायित्व है। प्रयोग करने के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। यह संघीय प्रणाली का एक सुखद पहलू है कि कोई एक साहसी राज्य, यदि उसके नागरिक चाहें, तो एक प्रयोगशाला बन सकता है; और नया सामाजिक एवं आर्थिक प्रयोग कर सकता है —– बिना पूरे राष्ट्र को खतरे में डाले।"

"इस न्यायालय के पास प्रयोग को रोकने की शक्ति है... लेकिन इस उच्च शक्ति के प्रयोग में हमें सदैव सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी पूर्वग्रहों (prejudices) को विधिक सिद्धांत में परिवर्तित कर बैठें।"
"न्यायालयों को प्रशासनिक नीति के उस 'हरित क्षेत्र' से बाहर रखा गया है, सिवाय तब के जब वह नीति उस विधि के स्पष्ट या अंतर्निहित प्रावधानों के विरुद्ध हो, जिसने वह शक्ति प्रदान की है जिससे वह नीति संबंधित है, या जब उस शक्ति के कथित प्रयोग में लिया गया निर्णय ऐसा हो, जिसे वह प्राधिकारी, यदि वह उचित और सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा हो, कभी न लेता।"
"ऐसी स्थिति में, न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई 'अत्यंत असाधारण' कारण उपस्थित हो। यह, और होना भी चाहिए, याचिकाकर्ता के लिए एक कठिन उत्तरदायित्व है।"
"न्यायालय नीति निर्माण या मूल्यांकन में कुशल नहीं हैं। कभी–कभी जब न्यायालयों ने नीति के आधार पर हस्तक्षेप किया है, तब उनके निर्णय सार्वजनिक स्वीकृति नहीं पा सके हैं। बल्कि, नीति पर न्यायालय के दृष्टिकोण की तीखी आलोचना हुई है। राजनीति की दुनिया में, न्यायालय की नीति पर राय, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों या विशेषज्ञ प्रशासकों की नीति से स्वाभाविक रूप से कम लोकप्रिय होती है... "
"उन विचारों के आधार पर कि कोई नीति कितनी 'उचित' है, उसका निर्धारण न्यायिक रूप से बहुत कम ही संभव होता है... "
"जैसा कि प्रोफेसर वेड बताते हैं, विधिक सीमाओं के भीतर पर्याप्त स्थान है जहाँ पर दो भिन्न मत हो सकते हैं —– और दोनों में से कोई भी 'अविवेकपूर्ण' नहीं होता।"

टेमसाइड मामले (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड साइंस बनाम मेट्रोपोलिटियाँ बोरोग़ ऑफ़ तमेसीदे, 1977 AC 1014: (1966) 3 All ER 665) में लॉर्ड डेनिंग ने इस त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया कि विचारों में भिन्नता को —– चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो —– किसी एक पक्ष की अयुक्तियुक्तता मान लेना गलत है।

लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा: "प्रशासनिक विवेकाधिकार की अवधारणा ही यह दर्शाती है कि कई संभावित कार्यवाहियों में से किसी एक को चुनने का अधिकार होता है, जिन पर तर्कसंगत लोग विभिन्न राय रख सकते हैं कि कौन–सा बेहतर है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

57. इसी संदर्भ में प्रशासनिक विधि(आठवाँ संस्करण) एच.डबल्यू.आर. वेड़ & सी.एफ. फ़ोर्सिथ द्वारा लिखित, पृष्ठ 776, पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया है:

“संविदात्मक दायित्वों को न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता (देखें पृष्ठ 624), जब तक कि यह प्रश्न न हो कि संविदा करने वाला प्राधिकरण अपनी शक्तियों से परे गया है। सरकार का बहुत सारा क्षेत्र अब संविदा के माध्यम से संचालित हो रहा है, जिससे यह निष्कासन नियम प्रशासनिक शक्ति के बड़े हिस्से को न्यायिक नियंत्रण से बाहर कर देता है, जो कि संविधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। (देखें [1994] PL 86, [1998] PL 288 {एम.फ्रीलैंड}; मरी हंट इन टैगर्ट (एड.),द प्रोविंस ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 21) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि न्यायालय अभी तक इस खतरे को लेकर सतर्क हैं।”

58. प्रोफेसर वेड ने पृष्ठ 776, पैरा 3 में आगे यह भी कहा:

“व्यवहारिक रूप से, कानून से इतर, सार्वजनिक प्राधिकरणों के अनुबंधों के कई ऐसे विशिष्ट पहलू होते हैं, जो भले ही सामान्य कानून के अनुसार व्याख्यायित और प्रवर्तनीय हों, फिर भी उन्हें नियमों के एक विशिष्ट निकाय का विषय माना जा सकता है। (देखें टर्नपिन, अध्याय 6–8)। केंद्र सरकार के अनुबंधों पर लाभ की दरें समीक्षा के अधीन होती हैं — या तो बढ़ाई जा सकती हैं या घटाई जा सकती हैं —
और यह या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट संविदा के लिए लागू हो सकता है —
जिसे सरकारी अनुबंधों के लिए समीक्षा बोर्ड द्वारा देखा जाता है।”

59. प्रो. वेड ने पृष्ठ 777 और 778 पर “संविदा निम्नप्रकार से विस्तार से चर्चा की है:

“संविदा के माध्यम से शासन सार्वजनिक प्राधिकरण अनुबंधों का उपयोग नीति निर्धारण और प्रशासन — दोनों उद्देश्यों के लिए करते हैं। (देखें तुरपिन, ब्रिटिश सरकार एवं संविधान, चौथा संस्करण, पृष्ठ 404; हार्डेन, द कांट्रैक्टिंग स्टेट; [1994] PL 86, [1998] PL 288 (एम. फ्रीलैंड)) स्थानीय प्राधिकरण अपने वैधानिक संविदा शक्तियों का उपयोग नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। नियोजन के क्षेत्र में, उन्हें भूमि के विकास या उपयोग को 'प्रतिबंधित या विनियमित' करने के लिए समझौते करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं (नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1990, धारा 106)। वे प्रायः योजना अनुमति के आवेदकों को कुछ रियायतों के लिए सहमत करवा लेते हैं जो वे वैधानिक शर्तों के माध्यम से थोपने की शक्ति नहीं रखते। इस प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न उठाए गए हैं, परंतु इसे वैध माना गया है (गुड बनाम इपिंग फॉरेस्ट डी सी [1994] 1 WLR 376; टेस्को स्टोर्स लिमिटेड बनाम सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर थे एनवायरमेंट [1995] 1 WLR 759 (HL))। स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निकायों के बीच प्रशासनिक सहयोग संविदा द्वारा किया जा सकता है, ताकि एक प्राधिकरण दूसरे की ओर से वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान कर सके (Local Government Act 1972, धारा 101)।”

60. प्रो. वेड (पृष्ठ 778, पैरा 3) ने भी आगे निम्नप्रकार से वर्णित किया हैं:

“सरकारी विभाग कई संविदा प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से देते हैं, जो यह सुनिश्चित करने की नीति के अनुरूप होता है कि जहाँ भी संभव हो, बाज़ार का परीक्षण किया जाए। (देखें उदाहरणार्थ: आर बनाम लॉर्ड चांसलर एक्स पार्टे हिबबिट और सॉन्डर्स [1993] कॉड 326; हार्लो और रॉलिंग्स, कानून और प्रशासन, द्वितीय संस्करण। एरोस्मिथ, द लॉ ऑफ पब्लिक एंड यूटिलिटीज प्रोक्योरमेंट, अध्याय 13)। स्थानीय प्राधिकरणों को भी ऐसा ही करने के लिए बाध्य किया गया है।” सरकारी विभागों के अपने वर्क्स डिपार्टमेंट्स को भी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा के अधीन किया जा सकता है। ग्राउंड मेन्टेनेंस, कचरा संग्रहण और वाहन रखरखाव जैसी सेवाएँ, 'अनिवार्य प्रतिस्पर्धी निविदा' के अधीन की गई हैं। लगातार लागू हुए स्थानीय सरकार अधिनियमों ने राज्य सचिव को यह शक्ति प्रदान की कि वे सूची का विस्तार कर सकें और अवज्ञाकारी प्राधिकरणों को 'प्रतिबंध आदेश' जारी कर सकें, जो उनके अधिकारों को प्रतिबंधित या विनियमित कर सकते हैं। (स्थानीय सरकार योजना एवं भूमि अधिनियम 1980, भाग II; स्थानीय सरकार अधिनियम 1988, भाग I और II (अब आंशिक रूप से निरस्त); स्थानीय सरकार अधिनियम 1992, भाग I; देखें: सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर एनवायरमेंट एक पक्षीय हरिंगे LBC (1994) 92 LGR 5388 — जहाँ राज्य सचिव का प्रतिबंध आदेश बरकरार रखा गया) यह कठोर प्रणाली 1999 में नीति परिवर्तन के बाद नरम कर दी गई, जिसमें यह कर्तव्य जोड़ा गया कि स्थानीय निकायों को 'सर्वश्रेष्ठ मूल्य' सुनिश्चित करना होगा। (स्थानीय सरकार अधिनियम 1999)

61. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि प्रो. वेड ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक विधि के आठवें संस्करण में स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह कहा है कि: "अंग्रेज़ी कानून में (फ्रेंच एवं अन्य देशों के विपरीत), सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए अनुबंधों को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष विधिक व्यवस्था नहीं है।" पूर्व में क्राउन की एक विशेष विधिक स्थिति थी और कुछ हद तक अभी भी है —— लेकिन जैसा कि प्रो. वेड ने संविदा में दायित्व शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया है, क्राउन कार्यवाही अधिनियम 1947 के तहत, अब क्राउन को अधिकांश व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए एक सामान्य वादी की तरह माना जाता है। इंग्लैंड में केंद्रीय सरकारी विभाग सामान्यतः अपने नाम से संविदा करते हैं, लेकिन वे क्राउन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिस कारण ऐसे अनुबंधों को लागू करना उक्त अधिनियम के अंतर्गत आता है। अन्य सरकारी निकाय जैसे स्थानीय प्राधिकरण भी इसी विधिक ढांचे के अधीन हैं। वे आमतौर पर संविदा के सामान्य विधि के अधीन होते हैं जो निजी व्यक्तियों और कंपनियों पर लागू होता है (हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद मौजूद है), जैसा कि प्रो. वेड द्वारा उल्लेख किया गया है।

62. यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में यह माना है कि:

"केवल इसलिए कोई संविदा 'वैधानिक' नहीं बन जाता क्योंकि वह किसी सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण से संबंधित है या किसी वैधानिक संस्था द्वारा दिया गया है।"

न्यायालय ने यह कहा: "हम श्री रावल के पहले तर्क में बल पाते हैं। विद्वान वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर सही प्रश्न उठाया है। संविदा की किसी धारा की व्याख्या और कार्यान्वयन रिट याचिका का विषय नहीं हो सकता। संविदा में भुगतान की व्यवस्था है या नहीं —— यह एक निवचनात्मक प्रश्न है। यदि संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन होता है, तो सामान्यतः उपचार रिट याचिका नहीं बल्कि अन्य विधिक उपाय होते हैं। हम इस मत से सहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता किसी वैधानिक संविदा को लागू करने की मांग कर रहा है। संविदा सिर्फ इसलिए वैधानिक नहीं बनता कि वह किसी वैधानिक निकाय द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता निर्माण हेतु दिया गया हो। उच्च न्यालय ने यह भी कहा कि चूंकि संविदा में लगाई गई शर्तें संविदा अधिनियम के अधीन आती हैं, इसलिए वह संविदा वैधानिक बनता है —— यह भी एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष है। स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती कर गया कि यह संविदा अपनी प्रकृति में वैधानिक है।"

इस न्यायालय की राय में, उपरोक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर समान रूप से लागू होता है।

63. जहाँ तक अतिविलंभ का प्रश्न है,

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की ओर से अतिविलंबता कारित किया गया है| 07.05.2003 को वाणिज्यिक निविदाएं सभी पक्षों की उपस्थिति में खोली गई थीं, हालांकि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता पर आपत्ति पहली बार 16.06.2003 को उठाई, अर्थात लगभग 40 दिनों के बाद, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता तकनीकी और वाणिज्यिक बैठकों में उत्तरवादीगण 1 से 3 के साथ उपस्थित होता रहा। 16.06.2003 को पहली बार याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण 1 से 3 को एक अभ्यावेदन सौंपा, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता पर आपत्ति जताई गई थी। इसके पश्चात जुलाई 2003 में कुछ और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। फिर, 07.07.2003 को दोनों पक्षों ने संशोधित मूल्य निविदाएं प्रस्तुत कीं। उच्चतम न्यायालय ने 'रामाना दयाराम शेट्टी' के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"यह समझना कठिन है कि अपीलकर्ता ने जब उत्तरवादी 4 की निविदा 19 अप्रैल 1977 को ही स्वीकार कर ली थी, तब प्रतीक्षा क्यों की और 08 नवम्बर 1977 को रिट याचिका दायर की।"

"इसके अतिरिक्त, रिट याचिका निविदा स्वीकार होने के पाँच महीने से अधिक समय बाद दायर की गई, और इस अवधि में उत्तरवादी 4 ने रेस्टोरेंट और स्नैक बार की व्यवस्था के लिए लगभग ₹1,25,000/– खर्च कर दिए थे, और वास्तव में स्नैक बार चालू कर दिए थे। अब ऐसे संविदा को निरस्त करना अन्यायपूर्ण होगा। स्थिति अलग होती यदि अपीलकर्ता ने निविदा स्वीकार होने के तुरंत बाद याचिका दायर की होती, लेकिन उसने पाँच महीने से अधिक का समय गंवा दिया, जिसके दौरान उत्तरवादी 4 ने अपनी स्थिति बदल ली। अतः हमारा मत है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमें हस्तक्षेक करना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग कर अपीलकर्ता को अनुतोष प्रदान करना चाहिए।"

High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने समय पर न्यायालय का रुख नहीं किया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार को उपयोग करने में देरी हुई।

64. जहाँ तक आवश्यक पक्षों को शामिल न करने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 के संघ के सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाया, इसके लिए कोई विधिसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने रामराव बनाम ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास एम्प्लॉयीज़ एसोसिएशन (2004 (2) SCC 76) के मामले में यह निर्णय दिया:

"स्वीकृत रूप से, यूनियन ऑफ इंडिया या नाबार्ड उक्त रिट याचिकाओं में पक्षकार नहीं थे। ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित करना, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया हो और जिसे सुनवाई का अवसर भी न दिया गया हो, विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। अपीलकर्ता, जिनके पक्ष में पदोन्नति के आदेश पारित हुए थे, और जिन्हें विवादित आदेश के द्वारा वापस लिया गया था, निस्संदेह आवश्यक पक्षकार थे। उनकी अनुपस्थिति में रिट याचिका का प्रभावी निर्णय नहीं किया जा सकता था।"

65. उत्तरवादीगण 1 से 3 के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेख में यह बात आ चुकी है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने जब निविदा प्रस्तुत की थी, तब यह स्पष्ट किया गया था कि निविदा दस्तावेज़ उसकी ओर से और मेसर्स एल. जीस्मार की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तथा दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था। निविदा दस्तावेज़ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि संघ समझौते को किसी विशेष प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए, यह दलील न्यायसंगत प्रतीत होती है| (Black's Law Dictionary, 7 वाँ संस्करण) में "कॉन्सॉर्शियम" को परिभाषित किया गया है — "एक ऐसा समूह जो किसी उद्यम के लिए एकजुट होकर कार्य करता है।" समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक समझौते को निष्पादित करने का तरीका है। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 ने यह दोहराया है कि उन्होंने उक्त समझौता ज्ञापन को स्वीकार किया है। संविदा सबसे कम बोली लगाने वाले को प्रदान किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता की बोली उच्चतर थी। कीमतों का अंतर पर्याप्त था, और उत्तरवादी क्रमांक 1 मूल्यांकन मापदंडों के अनुसार अर्हित था। 21.09.2003 को त्रिपक्षीय संविदा में लेटर ऑफ इंटेंट विलीन हो गया, जिसमें एक ओर भिलाई स्टील प्लांट था, और दूसरी ओर उत्तरवादी क्रमांक 4, तथा संघ के सदस्य — एल. जीस्मार और सीमेंस इंडिया पक्षकार थे। याचिकाकर्ता ने इन पक्षों को रिट याचिका में शामिल नहीं किया है, इसलिए इनकी अनुपस्थिति में संविदा और समझौते को रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह तर्क स्वीकार करने योग्य है कि उचित पक्षकारों को सम्मिलित नहीं किया गया।

66. बहस के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए प्रस्तावित कीमतें अत्यधिक और कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई थीं,जबकि आयातित उपकरणों की कीमत या अंतरराष्ट्रीय बाज़ार कीमत इससे बहुत कम थी। यह दावा किया गया कि पैकेज A में डिज़ाइन और इंजीनियरिंग लागत याचिकाकर्ता की तुलना में 15 गुना अधिक है, और पैकेज B के लिए 40% अधिक है। इसके समर्थन में तुलनात्मक मूल्य चार्ट प्रस्तुत किया गया है—

तुलनात्मक मूल्य तालिका

पैकेज A:

(i) डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग: याचिकाकर्ता: यूरो 36,381 + ₹19,75,867/– उत्तरवादी क्रमांक 4: यूरो 5,60,400 + ₹1,23,95,715/–

(ii) संयंत्र एवं उपकरण: याचिकाकर्ता: यूरो 16,02,608 + ₹1,05,10,959/– उत्तरवादी क्रमांक 4: यूरो 8,40,600 + ₹1,01,62,160/–

(iii) कुल (प्रशिक्षण, बीमा आदि सहित): याचिकाकर्ता: यूरो 17,24,942 + ₹2,12,09,249/–उत्तरवादी क्रमांक 4: यूरो 15,05,600 + ₹3,21,27,000/–

रुपयों में कुल मूल्य (बिना शुल्क व कर के): याचिकाकर्ता: ₹11.43 करोड़ उत्तरवादी क्रमांक 4: ₹11.34 करोड़

इसी प्रकार, पैकेज B के लिए कुल मूल्य (कर व शुल्क रहित): याचिकाकर्ता: ₹20.61 करोड़ उत्तरवादी क्रमांक 4: ₹17.50 करोड़

67. उपरोक्त तुलना संबंधी प्रश्नों को दूसरे पक्ष ने दृढ़ता से खारिज किया है

और यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पैकेज A और B दोनों को स्वीकार करने से कुल ₹6.48 करोड़ की बचत हुई है। यह ₹6.48 करोड़ की बचत विभिन्न सुनवाइयों में दोहराई गई और बार पर भी इसे पुष्ट किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हंसरिया ने यह कहा कि यह ₹6 करोड़ की बचत याचिकाकर्ता के लिए महत्वपूर्ण न हो, परंतु यह उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह आंकड़ा एक विशेषज्ञ निकाय की राय पर आधारित है। इस कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार में उन मुद्दों की जांच नहीं कर सकता, जो विवादित हों और जिनके लिए विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता हो।

68. निविदाएं 07.05.2003 को खोली गईं। अभिलेख से यह स्पष्ट है किउत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 लगातार याचिकाकर्ता के साथ तकनीकी एवं वाणिज्यिक पहलुओं पर बातचीत कर रहे थे, और यह दोनों पक्षों को ज्ञात था। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 दोनों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। बिड डेटा शीट केवल पूरे निविदा दस्तावेज़ का एक हिस्सा है, और संविदा की किसी भी धारा की व्याख्या पूरी निविदा दस्तावेज़ों को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए, ना कि किसी एक विशेष स्थान की किसी एक धारा को अलग से लेकर। इस न्यायालय का यह मत कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड.(पूर्वत) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निम्नलिखित अवलोकनों द्वारा पुष्ट होता है:

"यहां तक कि यदि निर्णय-लेने की प्रक्रिया में कोई दोष पाया जाता है, तो भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग अत्यंत सतर्कता के साथ करना चाहिए, और केवल सार्वजनिक हित की पूर्ति हेतु ही इसका प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ किसी कानूनी बिंदु की स्थापना के लिए नहीं। न्यायालय को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या व्यापक सार्वजनिक हित उसके हस्तक्षेप की मांग करता है या नहीं। केवल तभी, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सार्वजनिक हित का भारी दबाव हस्तक्षेप की माँग करता है, तभी न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

69. यह न्यायालय इस तथ्य से आँख नहीं मूँद सकता कि जी.बी. महाजन(पूर्वत) मामले में यह कहा गया है कि राज्य की व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में उपस्थिति का विस्तार,सरकारी आर्थिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की विविधता, सरकार की उस बढ़ती हुई चिंता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य है — दक्षता को बढ़ाना, लागत को कम करना, प्रबंधन विधियों में सुधार करना, परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता को रोकना, समयसीमा के साथ लागत का संतुलन साधना, गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखना, तथा लागत-लाभ अनुपात को सुनिश्चित करना। "इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु उपयुक्त तकनीकों को अपनाया जाए, जिनमें आर्थिक दृष्टिकोण भी सम्मिलित हो। ये सभी विषय आर्थिक नीति से संबंधित होते हैं, जिन पर न्यायिक निर्णय नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वे (i) स्पष्ट या निहित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करते हों, (ii) निर्णय लेने की शक्ति का दुरुपयोग न हो, (iii) और कोई अत्यंत असाधारण कारण न हो जो न्यायालय के हस्तक्षेप को आवश्यक बना दे। ऐसी स्थिति में न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई 'अत्यंत गंभीर कारण' प्रकट हो। यह एक कठिन उत्तरदायित्व है जिसे याचिकाकर्ता को सिद्ध करना होता है। न्यायालय नीति निर्माण और मूल्यांकन में विशेषज्ञ नहीं होते, और जब उन्होंने हस्तक्षेप किया है, तो कई बार उनके निर्णय व्यापक सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसलिए, न्यायालयों को प्रशासनिक नीति के उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि नीति स्पष्ट रूप से विधिक अधिकारों का उल्लंघन न करे, या दुर्भावना, भेदभाव, या मनमानेपन से ग्रसित न हो|

70. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह अधिकार इस मामले में प्रयोग किया जा रहा है कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 के पक्ष में निविदा स्वीकार की गई है। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने उत्तरवादी क्रमांक 4 और उसके संघ की निविदा को स्वीकार कर लिया है। दोनों निविदाएं स्पष्ट रूप से 07.05.2003 को प्रस्तुत और खोली गई थीं। याचिकाकर्ता ने 16.06.2003 को परिशिष्ट P-1 के अनुसार कुछ आपत्तियाँ उठाईं। 07.07.2003 को याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 दोनों को बातचीत के लिए बुलाया गया, बातचीत हुई, और दोनों ने संशोधित मूल्य निविदाएं प्रस्तुत कीं, जिन पर विचार किया गया। इन प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह स्थिति सामने आई कि पैकेज A और पैकेज B दोनों में उत्तरवादी क्रमांक 4 के कोटेशन कम हैं, और ₹6.48 करोड़ की बचत हो रही है। यहाँ सार्वजनिक हित के तत्व भी सम्मिलित हैं, क्योंकि

यह परियोजना सार्वजनिक धन से निष्पादित की जा रही है, और इसका क्रियान्वयन भारतीय रेल के लिए किया जा रहा है, तथा यह आपूर्ति भारतीय रेल को की जाएगी। इस संविदा की समयबद्ध पूर्ति में जनता की सीधी रुचि है, ताकि सेवाएं शीघ्रता से आम नागरिकों को उपलब्ध हो सकें। जनता कार्य की गुणवत्ता में भी रुचि रखती है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा से कम मूल्य वाली निविदा को स्वीकार किया गया,और इससे ₹6.48 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि की बचत हुई है। यह न्यायालय इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि परियोजना में देरी होने पर औद्योगिक विकास प्रभावित होता है, सामान्य जनता को कठिनाई होती है, और लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है।

71. निविदाओं के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति नियुक्त की गई थी। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से इस समिति ने सभी प्रस्तावों की जाँच की। यदि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो परियोजना में उल्लेखनीय देरी हो सकती है, जिससे लागत में इतनी अधिक वृद्धि हो सकती है कि न्यायालय के निर्णय से सार्वजनिक धन की जो भी बचत होनी थी, वह निष्प्रभावी हो जाए। उत्तरवादियों ने अभिलेख पर यह बात रखी है किप्रारंभ में यह परियोजना एक ही थी, परंतु बाद में इसे तीन भागों — A, B और C में विभाजित कर दिया गया। इस विषय में परियोजना की आवश्यकता, व्यावहारिकता, वित्तीय व्यवस्था और लागत–प्रभावशीलता पर गहन विचार–विमर्श किया गया था।

72. याचिकाकर्ता ने मूल्य निविदा में भाग लिया था। उसने संशोधित निविदा भी प्रस्तुत की थी, जो कि उत्तरवादी क्रमांक 4 की तुलना में अधिक थी। अब वह उसी उच्च बोली के बाद आपत्ति उठा रहा है। याचिका में विवादित तथ्य हैं। यह भी प्रासंगिक है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने संघ सदस्य की ओर से निविदा प्रस्तुत की थी, और समिति ने यह विचार किया कि मेसर्स जीस्मार, फ्रांस — पिछले पाँच वर्षों में पाँच मशीनें आपूर्ति करने की पात्रता को पूरा करता है। यह उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में केवल चार पक्ष ही उपलब्ध हैं, जो आधुनिक रेल वेल्डिंग मशीनों के निर्माता/आपूर्तिकर्ता हैं जिसमें याचिकाकर्ता और मेसर्स जीस्मार, फ्रांस (जो कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का संघ सदस्य है) शामिल हैं। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 ने, जैसा कि अनुच्छेद 226(3) के अंतर्गत आवेदन और उत्तर में उल्लिखित है, और बार में दोहराया गया, पूरे मामले के सभी पक्षों का विचारपूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने अपने शपथपत्र में यह कहा है कि उन्होंने हर दृष्टिकोण से विषय का गहन परीक्षण किया है। यह प्रतिवादियों का स्पष्ट मामला है कि दुनिया भर में केवल चार निर्माता उपलब्ध हैं, जो आधुनिक रेल वेल्डिंग मशीनें बनाते/आपूर्ति करते हैं जिसमें याचिकाकर्ता और मेसर्स जीस्मार, फ्रांस सम्मिलित हैं। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 के अनुसार, समिति ने यह विचार किया कि मेसर्स जीस्मार, फ्रांस — जो उत्तरवादी क्रमांक 4 का संघ सदस्य है पिछले पाँच वर्षों में पाँच मशीनों की आपूर्ति की पात्रता मानदंड को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, इन चार वैश्विक निर्माताओं में से एक वर्तमान में इस व्यवसाय में सक्रिय नहीं है, और दूसरे ने बोली प्रस्तुत नहीं की। यदि उत्तरवादी क्रमांक 4 का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं माना जाता,तो (a) उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास केवल एक ही पक्ष — अर्थात याचिकाकर्ता — शेष रह जाता, जिससे पहली जैसी स्थिति पुनः उत्पन्न होती, यह मूल्य में कटौती कराना और एकमात्र पक्ष के साथ निविदा को अंतिम रूप देना अत्यंत कठिन हो जाता। याचिका 01.11.2003 को दायर की गई थी। उस समय तक सब कुछ पूर्ण हो चुका था। यदि उत्तरवादी क्रमांक 4 का प्रस्ताव विचार में नहीं लिया जाता, तो: (c) कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती, और पुनः निविदा (re–tendering) द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 ने यह भी कहा है कि उस समय पुनः निविदा प्रक्रिया अपनाने से निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकते थे:

(i) वैश्विक निविदा, तकनीकी–वाणिज्यिक जांच/चर्चा आदि की पूरी प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली है, जो रेल वेल्डिंग संयंत्र की कमीशनिंग अनुसूची में और विलंब करती, और इससे लागत में अत्यधिक वृद्धि होती।

(ii) रेल वेल्डिंग संयंत्र के अन्य पैकेज आपूर्तिकर्ता भी अपने पैकेज की कमीशनिंग में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते थे।

(iii) चूंकि इस क्षेत्र में पक्ष सीमित थे, बार–बार पुनः निविदा करने से कम प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया की संभावना बनी रहती।

यह वे कारण थे जिन पर उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 ने विचार किया और सभी पहलुओं को समिति द्वारा ध्यान में रखा गया। याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। उसने 16.06.2003 को आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर विचार कर उसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 दोनों ने 07.07.2003 को संशोधित निविदा प्रस्तुत की, जो उसी दिन खोली गई। 21.08.2003 को

लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया और करार पर हस्ताक्षर किए गए। याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार कर उन्हें अस्वीकार किया गया। सभी पहलुओं पर गहन विमर्श के बाद निर्णय लिया गया। यह कहा नहीं जा सकता कि यह निर्णय जल्दबाज़ी में लिया गया। एक बार जब उत्तरवादी क्रमांक 4 को पात्र और योग्य माना गया, और याचिकाकर्ता की आपत्ति अस्वीकार कर दी गई, तो याचिकाकर्ता को तुरंत न्यायालय का रुख करना चाहिए था, बजाय इसके कि वह निविदा प्रक्रिया में भाग ले और संशोधित मूल्य निविदा प्रस्तुत करे।

73. उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह याचिका स्वीकृति और अधित्यजन के सिद्धांत से बाधित है। स्वीकृति के सिद्धांत का आधार यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिकार का समय पर प्रयोग न करना, विरोधी पक्ष को हानि पहुँचाता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले कुछ निर्णयों में शामिल हैं महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम बनाम बलवंत रेगुलर मोटर सर्विसेज (AIR 1969 SC 329) अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1967 SC 856) पन्नालाल बिनजराज बनाम भारत संघ (AIR 1957 SC 397) सुनिता अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य (2000 (2) SCC 615) का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहाँ याचिकाकर्ता लेक्चरर के पद के लिए चयनित हुई थीं, परंतु कुलपति ने चयन को निरस्त कर पुनः विज्ञापन देने का निर्देश दिया। पुनः विज्ञापन के बाद उन्होंने फिर से आवेदन किया और बिना किसी आपत्ति के चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार में भाग लिया। उसी दिन उन्होंने कुलपति के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुनिता अग्रवाल मामले में न्यायालय ने उसे कोई वैवेविक अनुतोष देने से इंकार कर दिया था। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पुष्टि किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वत) मामले में यह अवलोकन किया गया कि: सामान्यतः, कोई व्यक्ति जो किसी निम्न प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है और कार्यवाही में भाग लेता है बिना इस आधार पर आपत्ति उठाए कि उस प्राधिकरण को क्षेत्राधिकार नहीं है — वह, जब कार्यवाही में असफल हो जाता है, तब वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उस प्राधिकरण की क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। इस मामले में, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 दोनों ने 07.05.2003 को निविदा प्रस्तुत की। तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 4 दोनों ही पैकेज A और B के लिए पात्र हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 07.07.2003 को संशोधित मूल्य निविदा प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 की निविदा प्रक्रिया में सभी चरणों में भाग लिया, चर्चा एवं बैठकों में हिस्सा लिया और टेंडर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित रहा। केवल 21.08.2003 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने और संविदा पर विधिवत हस्ताक्षर होने के बाद, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 की पात्रता को चुनौती दी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकृति सिद्ध होती है।

74. अधित्यजन के सिद्धांत पर विचार किया गया है। कृष्ण लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1994 (4) SCC 422) में जहाँ यह माना गया कि जब किसी प्रावधान का उद्देश्य केवल किसी विशेष व्यक्ति की सुरक्षा या लाभ हो, तो वह व्यक्ति उस अधिकार को त्याग सकता है ताकि यदि त्याग से संबंधित तथ्य प्रमाणित हो जाएँ, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर याचिका को खारिज किया जा सकता है।

75. जहाँ तक न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रश्न है, न्यायालय की जाँच सिर्फ निर्णय-लेने की प्रक्रिया तक सीमित होती है। स्वीकृत रूप से, उत्तरवादी क्रमांक 4 का संघ सबसे कम बोलीदाता था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, विशेषकर टाटा सेलुलर (पूर्वत) सहित, जैसा कि ऊपर चर्चा में आया, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक अवरोध अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि केवल यह देखता है कि निर्णय किस प्रकार लिया गया। न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सुधारने की विशेषज्ञता नहीं होती। यदि वह ऐसा करता है, तो वह अपनी राय प्रतिस्थापित करेगा जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उसके पास आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होती। निविदा आमंत्रण की शर्तों को न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे करार के क्षेत्र में आती हैं। सामान्यतः, संविदा प्रदान करने का निर्णय विभिन्न चरणों की बातचीत के माध्यम से लिया जाता है। इस मामले में, निर्णय विशेषज्ञों की समिति द्वारा गुणात्मक रूप से लिए गए हैं। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3, किसी भी अन्य सरकारी इकाई की तरह, करार की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। न्यायालय ने इस पूरे मामले पर, जैसा कि ऊपर विस्तृत किया गया है, गहराई से विचार किया है, और यह मत व्यक्त करता है कि यह निर्णय न तो मनमाना है, न ही पक्षपातपूर्ण और न ही दुर्भावपूर्ण है।

76. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत हस्तक्षेप का उपयुक्त विषय नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता यदि चाहे तो सिविल वाद दायर कर सकता है, और यदि ऐसा वाद दायर किया जाता है, तो उसे इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार उसके अपने गुण–दोष के आधार पर निपटाया जाएगा। तदनुसार, यह याचिका निराकृत की जाती है।

77. अंत में, यह न्यायालय सभी पक्षों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई बहुमूल्य सहयोग की सराहना करता है।

सही /—

(फ़खरुद्दीन)

न्यायाधीश

दिनांक: 12/04/2004

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By:– Aman Ansari, Advocate.